(b) if so, the details thereof; and

(c) what measures are being taken by Government for the removal of such financial constraints for starting power projects in these States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) Khaperkhera Thermal Power Station Extension Stage II (2 × 210 MW), which had been sanctioned by the Planning Commission in June, 1988 could not be taken up for implementation due to financial constraints. It has now been offered by Maharashtra State Electricity Board (MSEB) for private sector participation. Starting of no power generation project in Gujarat has been delayed on account of financial constraints.

Improving the Structure of SEBs

5525. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the financial and accounting system and the method of preparation of balance sheets and type of book-keeping maintained by state electricity boards are age old;

(b) whether it is a fact that the present structure of the Boards is not conducive to development but is oriented more to Government way of working, as also to meet the social obligation of supplying electricity in subsidised way, at low cost;

(c) if so, whether Government are considering to bring about drastic changes in the State Electricity Boards; and

(d) what steps have been taken by Government to improve the structure of the state electricity boards, in the light of the amendments to the Electricity Supply Act?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Commercial Accounting System was introduced in the State Electricity Boards in 1985-86. A Working Group consisting of experts from the State Electricity Boards has been constituted to review the system.

(b) and (c) An NDC Committee on Power has been constituted to review the institutional and financial structure of the State Power Utilities and recommend necessary changes which would ensure that they would function on commercial lines with adequate customer-orientation.

(d) The Action Plan adopted by the Power Minister's Conference in January, 1993 provide, *inter-alia*, for conversion of part of the loans given by State Govts. to State Electricity Boards into equity.

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की ताप-विद्युत परियोजनाएं

5526. श्री रामजी लाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की विभिन्न ताप-विद्युत परियोजनाओं को निर्धारित समय के अन्दर पूरा न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इसके कारण परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में फरीदाबाद तथा अदुनानगर में ताप-विद्युत परियोजनाओं के सन्दर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को समय पर पूरा न किए जाने के परिणामस्वरूप देश में बिजली की कमी हो जाएगी; और

(घ) हरियाणा में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैय्या नायडू) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा न हो पाने के निम्नलिखित कारण हैं :—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	राज्य जिसमें अवस्थित है	क्षमता	विलम्ब के मुख्य कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना	उत्तर प्रदेश	4×210 फेरोवाट	यूनिट-2 टर्बोजेन-रेटर के उत्थापन की गति का धीमी होना यूनिट-3 टर्बोजेनरेटर के उत्थापन कार्य शुरू होने में विलम्ब

1	2	3	4	5
				यूनिट-4 अवसंरचनात्मक स्टील के उत्थापन कार्य/टर्बोजेनरेटर के कक्ष को तैयार करने में उत्थान कार्य की शुरूआत किए जाने में विलम्ब होना
2.	दादरी गैस आधारित सी०सी०जी०टी०	उ०प्र०	4×131 जी० टी०+ 2×146 एस०टी०	(क) आयातित सी० एण्ड आई/वैद्युत उपस्कर हेतु विदेशी मुद्रा के लिए साख पत्र खोजने में विलम्ब होना। (ख) डब्ल्यू०एच०आर०बी० के लिए मेल द्वारा उपस्कर सप्लाई करने में विलम्ब होना
3.	फरक्का एस०टी०पी०पी०	प० बंगाल	3×500 मे०वा०	1. बायलर का फेल होना। ई०एस०पी० का दह जाना। 2. यूनिट-6 के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता उपलब्ध न होना।
4.	कहलगांव एस०टी०पी०पी०	बिहार	4×210	1. 9.10.92 को विस्फोट के कारण बायलर क्षति ग्रस्त होना 2. तत्कालीन यू०एस०एस०आर० से शेष सामग्री सप्लाई किए जाने में विलम्ब होना।
5.	तलेचर एस०टी०पी०पी०	उड़ीसा	1×500 मेगावाट	1. कार्य स्थल पर औद्योगिक संबंधों की समस्याएं होना 2. शेष भूमि अधिग्रहण करना 3. उपस्कर सप्लाई न किया जाना

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं की समयावधि बढ़ जाने से इनकी लागत में वृद्धि हुई है। तथापि, यमुना नगर और फरीदाबाद परियोजना लागत अभिवृद्धि से प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अभी इन परियोजनाओं को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा न होने से विद्युत की उपलब्धता प्रभावित होगी।

(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने फरीदाबाद में 400 मेगावाट का संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र अधिष्ठापित करने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है। इसी बीच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति और गैस लिंकेज समेत अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं। परियोजना के लिए ओ०ई०सी०एफ० सहायता की प्रथम किस्त के रूप में, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विद्युत केन्द्र के हिस्से के लिए 19.998 मिलियन जापानी येन और पावर ग्रिड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे पारेषण हिस्से के लिए 3.538 मिलियन जापानी येन समेत ओ०ई०सी०एफ० जापान ने परियोजना के लिए 23.5 मिलियन जापानी येन के ऋण की सुविधा प्रदान की है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की हरियाणा के यमुना नगर में 840 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र अधिष्ठापित किए जाने की आयोजना थी, जिसे अब निजी क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

Thermal Power Plant at Basin Bridge in Tamil Nadu

5527. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to instal Thermal Power Plant at Basin Bridge in Tamil Nadu;